सरकार के साथ जारी रही तकरार

चार अनशनकारियों को पहुंचाया अस्पताल

परेड ग्राउंड स्थित धरना स्थल से आमरण अनशन पर बैठे पॉलीटेक्निक संविदा शिक्षकों को उठाने के बाद, विरोध करने वाले शिक्षकों को ले जाते पुलिसकर्मी। अमर उजाला

अमर उजाला ब्यूरो

देहरादून। सेवा विस्तार समेत विभिन्न मांगों को लेकर परेड ग्राउंड में अनशन पर बैठे पॉलीटेक्निक संविदा शिक्षकों को मंगलवार पुलिस ने उठाकर कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया। अनशन पर बैठे संविदा शिक्षकों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। चार अनशनकारियों पूनम रावत, दिव्या नेगी, मनीष भट्ट और पूरण राणा को अस्पताल पहुंचाए जाने के बाद दो अन्य शिक्षक सर्वेश चौधरी और गौरव भट्ट अनशन पर बैठ गए।

छात्रों ने सीईओ को घेरा

देहरादून। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने डीएवी इंटर कालेज में वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए सीईओ का घेराव किया। छात्रों ने कहा कि पीटीए मद में प्रति छात्र 450 रुपये लिए जाते हैं। इस बार बगैर बैठक ही धनराशि ली गई।

राजस्व संग्रह अमीनों का कार्य बहिष्कार जारी

देहरादून। प्रमोशन कोटा बहाल करने की मांग पर राजस्व संग्रह अमीनों का कार्य बहिष्कार मंगलवार पांचवें दिन भी जारी रहा। अमीनों ने कार्य बहिष्कार कर परेड ग्राउंड में धरना दिया। धरना देने वालों में महामंत्री वीरेंद्र सिंह सजवाण, रोशन लाल, बाबूलाल, भागेंद्र भंडारी, चंद्रवीर सिंह आदि शामिल थे।

आंदोलन की राह पर वन निगम कर्मचारी

देहरादून। वन विकास निगम के व्रिकय प्रभाग स्थित सेलाकुई डिपो की जमीन उत्तराखंड औद्योगिकी एवं वानिकी विवि भरसार से वापस निगम के नाम हस्तांतरित न किए जाने पर कर्मचारियों में भारी रोष है। मंगलवार को आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि 11 अगस्त तक पूर्व के समझौते के अनुरूप डिपो की भूमि का आवंटन न किया गया तो 12 अगस्त से प्रदेश मुख्यालय पर अधिकारियों का घेराव, अनिश्चितकालीन धरना और प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा।

सीएम से मिले प्रवर्तन सिपाही

देहरादून। परिवहन विभाग में कार्यरत प्रवर्तन सिपाही वर्षों से लंबित मांगों के समर्थन में मंगलवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत से मिले। इस दौरान सीएम को ज्ञापन सौंपते हुए उन्होंने मांगें जल्द पूरी करने की गुहार लगाई। प्रवर्तन कर्मचारी संगठन अध्यक्ष सुरेश चंद ने बताया कि प्रवर्तन सिपाहियों को मकान भत्ते के अलावा दूसरा भत्ता नहीं मिलता। पद सृजित न होने से वे एसीपी लाभ से वंचित हैं। सिपाहियों ने मांग की है कि आबकारी, वन और पुलिस विभाग की तरह प्रवर्तन सिपाहियों की भी नियमावली बने।

सीएम ने कर्मचारियों से कहा, हड़ताल प्रदेश न बनाएं

देहरादून। बीजापुर अतिथि गृह में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सीएम से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी। मुख्यमंत्री ने जायज मांगों के संबंध में मुख्य सचिव को 15 दिन में कार्रवाई को कहा है। मुख्यमंत्री ने कर्मचारी संगठनों से कहा कि प्रदेश को हड़ताल प्रदेश न बनाएं। वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि केंद्र स्तर पर 7वें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी हो रही है। सभी संगठन अपने सुझाव वेतन आयोग को भेजें। कर्मचारियों के हित में राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की स्थापना करके हेल्थ स्मार्ट कार्ड योजना को प्रभावी बनाया जाएगा। मुलाकात करने वालों में सचिवालय अधिकारी कर्मचारी संघ, नर्सेज संघ, राज्य कर्मचारी संयुक्त संगठन, डिप्लोमा फार्मासिस्ट संगठन, चतुर्थ कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि प्रमुख मौजूद थे।

प्रबंधन के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ आज

देहरादून। ओएनजीसी अस्पताल से निकाले गए संविदा कर्मी आज (बुधवार) को प्रबंधन की सद् बुद्धि और सुख-शांति के लिए यज्ञ करेंगे। उधर, पांच सूत्रीय मांगों पर संविदा कर्मियों का धरना पांचवें दिन मंगलवार को भी जारी रहा। कर्मियों का आरोप है कि एक भी दिन ओएनजीसी अफसरों ने उनकी कोई सुध नहीं ली। कर्मचारियों ने बताया कि स्टाफ निकालने से ओएनजीसी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं।

राजकुमार ने दी चमन को बधाई

देहरादून। जिपं अध्यक्ष पद पर चमन सिंह की जीत पर विधायक राजकुमार और सुबोध उनियाल ने चमन के घर जाकर उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। कांग्रेस प्रत्याशी की जीत उसकी जन कल्याणकारी नीतियों का नतीजा है।

COSMETICS FACTORY REQUIRED

We are looking to buy a fully operational cosmetics factory with a minimum area of 4000 sq. mtrs. The factory should be located in an Excise Free Zone.

Please contact at:
purchasenewfactory@gmail.com

नए अनुभागों के सृजन पर सचिवों का सरेंडर

अमर उजाला ब्यूरो

▶ और उग्र हो सकता है सचिवालय कर्मियों का आंदोलन

देहरादून। समीक्षा व सहायक समीक्षा अधिकारी संघ के कार्य बहिष्कार के मुद्दे पर मुख्य सचिव की बैठक नहीं हो सकी।

उधर, कर्मचारी आज भी सरकार पर जमकर बरसे और चार घंटे का कार्य बहिष्कार रखा। इस बीच सभी विभागों के प्रमुख सचिव व सचिवों ने मुख्य सचिव को भेजी गई रिपोर्ट में कहा है कि नए अनुभाग सृजित नहीं होने चाहिए क्योंकि पहले के सेक्शन अभी तक क्रियाशील नहीं हुए हैं। सचिवालय प्रशासन ने मुख्य सचिव को अन्य दो राज्यों की तुलनात्मक रिपोर्ट भी भेजी है। समीक्षा अधिकारियों के आंदोलन में तकनीकी तौर पर कई तथ्य चुनौती पेश करने वाले हैं। मसलन उत्तराखंड से यूपी बीस गुना बड़ा है और वहां पौने चार सौ अनुभाग हैं। झारखंड भी उत्तराखंड की तिगुना है लेकिन वहां अनुभागों की संख्या मात्र 93 है। उत्तराखंड में 141 अनुभाग हो चुके हैं। इस बीच सचिव व प्रमुख सचिवों ने मंगलवार को मुख्य सचिव को भेजी रिपोर्ट में कहा है कि अब और अनुभाग बनाए जाने की जरूरत नहीं है। अब बुधवार को मुख्य सचिव सुभाष कुमार अफसरों के साथ विचार विमर्श करने के बाद आंदोलनरत कर्मियों को वार्ता के लिए बुलाएंगे।

विभिन्न राज्यों के सचिवालयों में अनुभागो की संख्या

उत्तर प्रदेश	375
झारखंड	93
हिमाचल प्रदेश	100
उत्तराखंड	141

(14 नए अनुभाग खोलने की मांग है)

निगम कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से की मुलाकात

देहरादून। राज्य के सभी निगमों के राजकीयकरण करने की मांग राज्य निगम कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री की है। प्रतिनिधिमंडल संतोष रावत की अध्यक्षता में मंगलवार को सीएम से मिला। महासंघ ने आपदा के दौरान निगमों को पहुंचे नुकसान के लिए कोई मदद नहीं मिलने के साथ ही प्रबंध निदेशकों के तबादलों का मुद्दा उठाया। महासंघ का मानना है कि निगमों को समाप्त कर उनको राजकीय विभाग का दर्जा दे देना चाहिए। सीएम हरीश रावत ने आश्वस्त किया है कि इसकी व्यवस्था बनाई जा रही है। महासचिव रवि पचौरी ने बताया कि सीएम ने कहा कि निगम एमडी का पद दो वर्ष के लिए किया जाएगा। ब्यूरो

कार्यालयः जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.), रुद्रप्रयाग

पृ.सं.: प्रा.शि./1173-74/वरि./2014-15 दिनांक 05 अगस्त, 2014

विज्ञप्ति

जनपद रुद्रप्रयाग के प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित समस्त अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि उनकी संशोधित वरिष्ठता सूची संबंधित उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है। इसे www.rudraprayag.nic.in पर भी देखा जा सकता है। विज्ञप्ति संख्याः प्रा.शि./791-92/वरिष्ठता/2014-15 दिनांक 03 जून 2014 के क्रम में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण कर संशोधित सूची तैयार की गयी है। जिन प्रत्यावेदनों के साथ वांछित साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये उनका निस्तारण नहीं हो सका है। अतः वरिष्ठता से संबंधित प्रत्यावेदन साक्ष्यों सहित दिनांक 13 अगस्त 2014 तक उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध कराये जा सकेंगे। यह अन्तिम अवसर है। इसके पश्चात प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)
रुद्रप्रयाग

राजकीय एजेंसी में समायोजित किया जाने की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय ननूरखेड़ा में झाड़ू लगाते रमसा के कार्यालय सहायक और प्रयोगशाला सहायक आउट सोर्सिंग कर्मचारी। अमर उजाला

सीएम से रोडवेज के लिए मांगे 22 करोड़

अमर उजाला ब्यूरो

● कर्मचारी इंप्लाइज यूनियन और संयुक्त परिषद मिले

देहरादून। रोडवेज कर्मचारी इंप्लाइज यूनियन और रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का अलग-अलग प्रतिनिधिमंडल मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री हरीश रावत से मिला। मुख्यमंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। यूनियन के प्रदेश महामंत्री रवि पचौरी ने बताया कि राज्य में आई आपदा का जख्म रोडवेज निगम को भी लगा है। लाखों रुपयों का नुकसान निगम झेल रहा है। इस संबंध में निगम प्रबंधन भी मुख्यमंत्री से पूर्व में मिल चुका है। पचौरी ने मुख्यमंत्री से 22 करोड़ रुपये की मांग की। वहीं रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश महामंत्री विजय कुमार ममगाई और क्षेत्रीय मंत्री राम चंद्र रतूड़ी भी इन्हीं मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिले। क्षेत्रीय मंत्री रतूड़ी ने बताया कि नई बसों की खरीद के संबंध में भी मुख्यमंत्री से वार्ता की गई।

पश्चिम रेलवे

निविदा सूचना सं.: सी78/1/117/एसएलआर/02/2014 दिनांक 24.07.2014 हेतु शुद्धि-पत्र

1) क्र. सं. 34 व 35 में गाड़ी सं. 12943 के एफएसएलआर-I एवं आरएसएलआर-III हेतु निविदा को निरस्त किया हुआ माना जाए। 2) क्र. सं. 74 व 75 में गाड़ी सं. 19045 के मामले में, "स्टेशन तक" में "वाराणसी" के बजाए "छपरा" पढ़ा जाए। 3) पैरा-1 में निविदा दस्तावेज के निर्गमन की समाप्ति की तिथि "20.08.2014" के बजाए "02.09.2014" पढ़ी जाएं। 4) पैरा-1 में निविदा प्रस्तावों की प्राप्ति तथा निविदा दस्तावेज खोले जाने की तिथि "21.08.2014" के बजाए "03.09.2014" पढ़ी जाएं। 5) अन्य समस्त निबंधन व शर्तें यथावत् रहेंगी।

यात्रियों की सेवा में मुस्कान के साथ 331

राज्य औषधीय पादप बोर्ड, उत्तराखण्ड
94, वसन्त विहार फेज-2, देहरादून-248006
टेलीफैक्स-0135-2769918, ईमेल-undpgefuk@gmail.com
वेबसाइट: www.smpbuk.org

विज्ञप्ति

राज्य औषधीय पादप बोर्ड, उत्तराखण्ड में औषधीय एवं सगन्ध पादपों के विकास हेतु सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत संचालित परियोजना प्रस्तावों के अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु राज्य स्तरीय परियोजना अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन समिति का गठन कर दिया गया है। सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं से सम्बन्धित जानकारी राज्य औषधीय पादप बोर्ड, उत्तराखण्ड की विभागीय वेबसाइट www.smpbuk.org पर देखी जा सकती है।

अधिक जानकारी के लिए कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी दूरभाष संख्या 0135-2769918 पर सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

....तो प्राधिकरणों में अस्थायी कर्मियों के आएंगे अच्छे दिन

देहरादून। प्रदेश के सभी प्राधिकरणों में तैनात अस्थायी कर्मचारियों के अच्छे दिनों आ सकते हैं। यह कर्मचारी राज्य विकास प्राधिकरण में स्थायी हो सकते हैं। साथ ही सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों उत्तरप्रदेश की तर्ज पर पेंशन भी दे सकती है।

मंगलवार को शहरी आवास विकास मंत्री से मिले मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण कर्मचारी संयुक्त संगठन का प्रतिनिधिमंडल को इस बाबत आश्वासन मिला है। संयुक्त संगठन के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश राणाकोटी ने बताया दो बिंदुओं के मांग पत्र को लेकर मंत्री प्रीतम सिंह से मिला। राज्य भर में 112 अस्थायी कर्मचारी हैं। यह बीस साल से ज्यादा सेवाएं दे रहे हैं। मांग पर मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रतिनिधि मंडल में शैलेंद्र राणा, टीएस पंवार, सत्यनारायण भट्ट शामिल थे। ब्यूरो

काम किया पर पुरानी सीट नहीं छोड़ीं

देहरादून। मिनिस्ट्रीयल कार्मिक मंगलवार को काम पर तो लौट आए लेकिन अपनी पुरानी सीटों पर ही काम किया। दिन भर सीटों के लिए खींचतान की स्थिति रही। जिन कार्मिकों ने नए पटल पर ज्वाइनिंग दे दी थी, उन्हें बैठने के लिए सीट नहीं मिली। उन्हें पुरानी सीट पर ही काम करना पड़ा। इन कार्मिकों ने अधिकारियों से शिकायत की। स्टाफिंग पैटर्न संबंधी आदेश की वापसी के बाद मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों ने हड़ताल खत्म कर दी थी। लेकिन उन्होंने तबादला आदेश के मुताबिक काम नहीं किया। कार्मिकों ने अपनी पुरानी सीटों पर ही काम किया। उनका कहना था कि स्टाफिंग पैटर्न के साथ तबादला आदेश भी निरस्त हो गया है। कार्मिकों के पटलों के संबंध में फेरबदल का नया आदेश आने के बाद वे सीटों पर जाएंगे। ब्यूरो

पंचायतीराज निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 684/ 3-पं./ ग्रा.पं./ शपथ - बैठक/ 2014-15 देहरादूनः दिनांक 5 अगस्त, 2014

::विज्ञप्ति::

शासनादेश संख्या 1780/XII (1)/2014-86(04)/ 2008 T.C.-1 दिनांक 31 जुलाई, 2014 के द्वारा राज्य के 12 जनपदों (हरिद्वार छोडकर) में नव निर्वाचित प्रमुखों/ क्षेत्र पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण एवं क्षेत्र पंचायतों की प्रथम बैठक तथा नव निर्वाचित अध्यक्ष गणों/ जिला पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण व जिला पंचायतों की प्रथम बैठक की तिथियाँ निम्नवत निर्धारित की गई हैः-

प्रमुख/ क्षेत्र पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण -	08 अगस्त, 2014 तक
क्षेत्र पंचायतों की प्रथम बैठक -	09 अगस्त, 2014
अध्यक्ष/ जिला पंचायत सदस्यों का शपथ ग्रहण -	11 अगस्त, 2014 तक
जिला पंचायतों की प्रथम बैठक -	12 अगस्त, 2014

उक्त के प्ररिप्रेक्ष्य में राज्य के (हरिद्वार छोडकर) समस्त नव निर्वाचित अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष / जिला पंचायत सदस्यों तथा प्रमुख/ उप प्रमुख/ क्षेत्र पंचायत सदस्यों से अनुरोध है कि जिलाधिकारियों (हरिद्वार छोडकर) द्वारा निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होने का कष्ट करें। साथ ही शासन द्वारा निर्धारित क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत की प्रथम बैठकों में भी प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

(ज्योति नीरज खैरवाल)
निदेशक

अमर उजाला APPOINTMENTS

बी.एड. प्रवेश हेतु पंजीकरण

नालन्दा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मियांवाला तिराहा, हरिद्वार रोड, देहरादून

(An ISO 9001 : 2008 Certified and NAAC 'B' accredited Institute)

हे.न.ब.ग. विश्वविद्यालय, श्रीनगर की बी.एड. प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्रा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित फीस पर सत्र 2014-15 में प्रवेश हेतु पंजीकरण करा सकते हैं।

पंजीकरण का समय- प्रातः 10 से 3 बजे तक।

सम्पर्क करें:- 0135-2688985, 9997974944
9760975309, 9412007407 प्रबन्धक

लेखक के निधन पर शोक

देहरादून। अजबपुर कलां स्थित शिरोमणि सत्संग भवन में दलित साहित्य एवं सांस्कृतिक अकादमी की आपात बैठक बुलाई गई। इस मौके पर दलित लेखक प्रोफेसर तेज सिंह के निधन पर शोक प्रकट किया गया। सभा की अध्यक्षता करते हुए सुनील कुमार ने कहा कि तेज सिंह का निधन दलित साहित्य के लिए अपूर्णनीय क्षति है। इस मौके पर बनवारी लाल, लोकेश कुमार, ध्वजवीर सिंह आदि उपस्थित थे।

कार्यालय निदेशक, महिला डेरी विकास परियोजना, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

निविदा सूचना

निदेशक महिला डेरी विकास उत्तराखण्ड अल्मोड़ा द्वारा निष्प्रोज्य वाहन (स्वराज माजदा मिनी बस) वाहन की नीलामी हेतु जहां है जैसे हैं के आधार पर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा फार्म शर्तों सहित निदेशक, महिला डेरी विकास उत्तराखण्ड जाखनदेवी अल्मोड़ा के कार्यालय से दिनांक 05.08.2014 से 25.08.2014 को सायं 5.00 बजे तक कार्यालय कार्य दिवसों ₹ 200.00 (दो सौ ₹ मात्र) तथा 4.5 प्रतिशत वैट अतिरिक्त कुल ₹ 209.00 (दो सौ नौ ₹ मात्र) नकद भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा फार्म यू.सी.डी.एफ.लि. की वेबसाइट www.ucdfanchal.org से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं।

शीलबंद निविदाएं दिनांक 26.8.2014 को दिन के 2.00 बजे तक निदेशक महिला डेरी विकास उत्तराखण्ड जाखनदेबी अल्मोड़ा के कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त की जाएगी, जो उसी दिन 3.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख खोली जाएंगी। किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को स्वीकृत/ अस्वीकृत करने का अधिकार संस्था के पास सुरक्षित रहेगा। इच्छुक निविदादाता वाहन का निरीक्षण महिला डेरी प्रशिक्षण केन्द्र कर्नाटकखोला अल्मोड़ा में कर सकते हैं। वाहन अर्नेष्ट मनी ₹ 10,000.00 (दस हजार ₹ मात्र) होगी।

क्र.सं.	वाहन संख्या	पेट्रोल/डीजल चालित	माडल एवं वर्ष
1.	यू.पी.001 4439	डीजल	स्वराज माजदा
			1998 माडल

निदेशक
महिला डेरी विकास उत्तराखण्ड
जाखनदेबी अल्मोड़ा

राजा महेन्द्र प्रताप प्रेम विद्यालय इण्टर कालेज, गुरुकुल नारसन, हरिद्वार, उत्तराखण्ड

विज्ञापन सं0/—01 **आवश्यकता है** दिनांक—06 अगस्त 2014

विद्यालय में निम्नलिखित पदों पर निम्नानुसार नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं—

प्रवक्ता (वेतन क्रम—9300—34800 ग्रेड पे— 4800)

नागरिक शास्त्र	— 1 पद	— (अनुसूचित जाति)
रसायन विज्ञान	— 1 पद	— (सामान्य जाति)
जन्तु विज्ञान	— 1 पद	— (सामान्य जाति)
भौतिक विज्ञान	— 1 पद	— (सामान्य जाति)
संस्कृत	— 1 पद	— (सामान्य जाति)

(प्रवक्ता रसायन का पद रिट सं0—1158/एस0एस0/2013 एवं प्रवक्ता संस्कृत का पद रिट सं0— 223/एस0एस0/2014 मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल के आदेश के अधीन प्रभावित रहेगी।)

स0अ0 एल0टी0 (वेतन क्रम — 9300—34800 ग्रेड पे — 4600)

हिन्दी	—02 पद (सामान्य जाति—01, अनुसूचित जाति—01)
अंग्रेजी	—02 पद (सामान्य जाति महिला—01, अनुसूचित जाति—01)
गणित	—02 पद (सामान्य जाति—01, अनुसूचित जाति—01)
विज्ञान	—02 पद (सामान्य जाति—01, अनुसूचित जाति—01)
सामाजिक विज्ञान	—02 पद (अनुसूचित जाति—01 स्वतंत्रता सैनानी आश्रित—01)
संस्कृत	—01 पद (सामान्य जाति)

शैक्षिक योग्यता एवं अन्य अर्हतायें—

1— प्रवक्ता पद — सम्बन्धित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र से स्नातक की उपाधि (बी0एड0) उत्तीर्ण हो।

2— स0अ0 एल0टी0— गृह विज्ञान छोड़कर अन्य सभी पदों हेतु आवश्यक रूप से टी0ई0टी0—2 उत्तीर्ण के साथ सम्बन्धित विषय में किसी राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय से कम से कम एल0टी0 डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र से स्नातक की उपाधि (बी0एड0) उत्तीर्ण हो।

अन्य शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हतायें उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम 2006 के अन्तर्गत निर्मित प्रख्यापित विनियम 2009 के निहित वर्णित प्राविधानों के अनुसार मान्य होगी तथा वेतन अन्य भत्ते राज्य सरकार द्वारा समय—2 पर अनुमन्यता के अनुसार देय होंगे। दर्शाये गये पदों पर क्षैतिज आरक्षण व उर्ध्वाधर आरक्षण नियमानुसार देय है/होगा साथ ही पूर्व में प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 15.08.2012 में स0अ0 कला एवं प्रवक्ता के पदों को छोड़कर अन्य विज्ञापित पदों पर प्रकाशित विज्ञप्ति को टी0ई0टी0—2 की बाध्यता के कारण निरस्त समझा जाये।

आवेदन पत्र कार्यालय, मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार से सभी पदों हेतु मात्र रू0—300 (तीन सौ) प्रति आवेदन पत्र रेखांकित पोस्टल आर्डर या बैंक ड्राफ्ट जो मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार के पदनाम से हो और डाकघर रोशनाबाद व स्टेट बैंक रोशनाबाद, में देय हो प्राप्त किया जा सकता है। विज्ञापन प्रकाशित होने की तिथि से तीन सप्ताह के अन्दर आवेदन पत्र मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार के कार्यालय में जमा होंगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर एवं अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। सभी शैक्षिक/प्रशिक्षण एवं अनुभव आदि अन्य प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित हों आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाये। **आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष** एवं उत्तराखण्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए साथ ही उत्तराखण्ड सेवायोजन कार्यालय में विज्ञप्ति से पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक से ही मान्य होगें। आवेदन पत्र के लिफाफे के बायी ओर पदनाम एवं दायी ओर विद्यालय का नाम अंकित होना चाहिए। बिना इनकी अंकना के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगें।

अनुभव प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0.....पुत्र/पुत्री श्री.....ने संस्था .....में ....पद पर दिनांक.....से .....तक.....कार्य किया है/कर रहे हैं। इस अवधि में इनको वेतन का भुगतान विद्यालय की रोकड पंजिका संख्या/.....बैंक के माध्यम से किया गया है। इनका खाता सं0.....है/था।

हस्ताक्षर व मोहर
नाम— ..... पद— .....
प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य/प्रबन्धक
संस्था का नाम .....

(अनुभव प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही मान्य होगा।) **(प्रबन्धक)**

खबरें तो हैं हर जगह, सिर्फ हम बताते हैं उसका मतलब: amarujala.com

कार्यालय जिला पंचायत, रूद्रप्रयाग।

संख्या 290/ नि.-08/ टे./ 2013-14 **निविदा सूचना** दिनांक 01/08/ 2014

जिला पंचायत रूद्रप्रयाग में राज्य वित्त अनुदान वर्ष 2013-14 के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु जिला पंचायत रूद्रप्रयाग के पंजीकृत ठेकेदारों से शीलबन्द निविदाऐं 20/08/2014 को 2.00 बजे अपराह्न तक आमन्त्रित की जाती है, जो उसी दिन 4.00 बजे सांय को उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष खोली जायेगी। निविदा के साथ 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र/ बैंक की एफ.डी.आर. के रूप में अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत रूद्रप्रयाग के पद नाम से बन्धक कर प्रस्तुत करनी होगी। जिला पंचायत की ओर से किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/ अस्वीकृत करने का अधिकार प्रशासक/ मा. अध्यक्ष, जिला पंचायत, रूद्रप्रयाग में निहित होगा। प्रत्येक निविदा के साथ रूपये 100.00 का नान जूडिसियल स्टाम्प पेपर व 1.00 रूपये का रसीदी टिकट लगाकर ठेकेदार द्वारा हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र दिनांक 19/08/2014 को अपराह्न 2.00 बजे तक जिला पंचायत के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है। प्रत्येक निविदादाता को निविदा प्रपत्र में अपनी दरों का प्रतिशत में स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

क्र.सं.	कार्य का नाम	आंगणन की धनराशि लाख रू. में	धरोहर धनराशि रू. में	निविदा की बैधता	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रपत्र का शुल्क/बिक्रीकर	श्रेणी
1.	जिला पंचायत कार्यालय भवन के द्वितीय तल पर कार्यालय कक्षों का निर्माण	9.85	19700	30 दिन	60 दिन	1000+13.50%	ए

शेष शर्तेः-1. सशर्ते निविदा/ अपूर्ण निविदा को स्वीकार नही किया जायेगा।
2. निविदा के साथ ठेकेदार को अपना पैन कार्ड न. एवं टीन.न. की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा बिक्रय एवं खोलने की तिथि को अवकाश होने की दशा में, निविदा अगले कार्यदिवस में बेची/ खोली जायेगी।
4. अन्य शर्ते किसी भी कार्यदिवस में जिला पंचायत कार्यालय में देखी जा सकती है।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, रूद्रप्रयाग।

कार्यालय चमोली जिला सहकारी बैंक लि.

चमोली जिला सहकारी बैंक लि. व समस्त शाखाओं में नये अग्निशमन यंत्रों की खरीद एवं पुराने यंत्रों की रिफलिंग का कार्य किया जाना है जिस हेतु निम्न शर्तों पर सील्ड निविदा आमंत्रित की जाती है।

1. फर्म/डीलर पंजीकृत हो।
2. फर्म/डीलर द्वारा राज्य/केन्द्र/निगमों/सहकारी संस्थाओं में अग्निशमन यंत्रों की रिफलिंग का कार्य किया हो।
3. फर्म/डीलर नियमानुसार सेल टैक्स/इन्कम टैक्स अदा करता हो।
4. फर्म/डीलर को डीलरशिप लेटर प्रस्तुत करना होगा।
5. आई.एस.आई. सर्टिफिकेट एक्यूपमेंट के साथ जमा करना होगा।
6. आई.एस.आई. मार्क संयंत्र में इन्ग्रेव होना चाहिए।
7. समस्त पुराने फायर संयंत्रों को शाखाओं में शाखा प्रबन्धकों/प्रधान कार्यालय के अधिकारियों के सामने खाली कर पुनः भरना होगा।

इस हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है तथा निविदा के साथ मु. 5000.00 की धरोहर राशि, जो सचिव/महाप्रबन्धक के नाम बंधक होगी, संलग्न करनी अनिवार्य होगी।

निविदायें दिनांक 16.08.2014 तक चमोली जिला सहकारी बैंक लि., मुख्यालय गोपेश्वर में दोपहर 12.00 बजे तक जमा की जा सकती है तथा निविदा उसी दिन सायं 1.00 बजे निविदाकर्ताओं/प्रतिनिधियों अथवा उनकी अनुपस्थिति में सचिव/महाप्रबन्धक के कार्यालय में खोली जायेगी। क्रय कमेटी को निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

सचिव/महाप्रबन्धक
चमोली जिला सहकारी लि.
प्र.का. गोपेश्वर

जिला सहायक निबंधक
सहकारी समितियां उत्तराखण्ड
चमोली